

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	<p>पौष 06, सोमवार, शाके 1943-दिसम्बर 27, 2021 <i>Pausa 06, Monday, Saka 1943- December 27, 2021</i></p>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

आदेश

जयपुर, दिसम्बर 27, 2021

चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी का नियमितिकरण हेतु पॉलिसी

संख्या प.2(17)राज-3/2021/151 :-राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(28) में चारागाह भूमि को परिभाषित किया गया है। जो इस प्रकार है:-

“चारागाह भूमि से वह भूमि अभिप्रेत है जो गांव या गांवों के पशुओं को चराने के उपयोग में लायी जाती है या जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय से इस रूप में बंदोबस्त अभिलेखों में अभिलिखित है या राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार बाद में इस रूप में आरक्षित की जाये।”

चारागाह भूमि शामिल होती भूमि होती है जिसका प्रबन्धन ग्राम पंचायत का होता है। यह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। संक्षिप्त में चारागाह भूमि को सीधे ही किसी अन्य प्रयोजन के लिये आवंटन नहीं किया जा सकता है। यदि चारागाह भूमि का कृषि या किसी अकृषि प्रयोजन के लिये आवंटन अपेक्षित हो तो भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन किया जाकर सिवायचक दर्ज किये जाने के उपरांत ही आवंटन किया जा सकता है। इस संबंध में प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में प्रावधित है।

चारागाह भूमि शामिल होती भूमि होने से इसके संरक्षण एवं अवैध कब्जेधारियों से मुक्त रखे जाने के लिये समय-समय पर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में आवश्यक निर्देश प्रदान किये जाते रहे हैं। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/2011 एस.एल.पी.(सी) संख्या 3109/2011 जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.1.2011 व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल याचिका (पी.आई.एल.) संख्या 1554/04 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2017 एवं 08.08.2017 मुख्य है। उक्त प्रकरणों में पारित निर्णयों के परिपेक्ष्य में महाधिवक्ता महोदय से चारागाह भूमि पर बसी आबादी को नियमित किये जाने पर विचार किये जाने से पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं पर राय प्राप्त की गई:-

1. चारागाह भूमि जिन पर लम्बे समय से अतिक्रमण कर पक्के या कच्चे आवासो का निर्माण कर लिया गया है तथा उसे आवासीय प्रयोजन से कार्य में लिया जा रहा है, का वर्गीकरण परिवर्तन कर सिवायचक भूमि में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा नहीं।
2. साथ ही कतिपय ग्रामों में चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है उक्त स्थिति में चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जा सकती है।

महाधिवक्ता से प्राप्त राय के परिपेक्ष्य में चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी को बेदखल किये जाने के स्थान पर नियमितिकरण किये जाने की पॉलिसी का अनुमोदन मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 157/2021 दिनांक 20/12/2021 द्वारा किया गया है। अतः मंत्रिमण्डल की आज्ञा के परिपेक्ष्य में चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी को नियमित किये जाने के लिये निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

1. चारागाह भूमि पर दिनांक 01.01.2021 तक जो व्यक्ति कम से कम 35 वर्ष पूर्व से आवास गृह बनाकर निवास कर रहे हैं उन अतिक्रमणों को तहसीलदार द्वारा चिन्हित कर सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में ऐसी चिन्हित भूमि का खसरा नं० एवं अतिक्रमित कर निर्मित आवास गृहो का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शे की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हैं, का समावेश होगा।
2. दिनांक 01.01.2021 से पूर्व चारागाह भूमि पर निर्मित आवास गृह की सूची तैयार करते समय राशनकार्ड, मतदाता सूची, बिजली/पानी/टेलिफोन बिल इत्यादि में से कोई एक दस्तावेज अवश्य संलग्न कराये जाये, जिससे कि यह विदित हो सके कि परिवार दिनांक 01.01.1986 से पूर्व से निवास कर रहा है।
3. उक्त तैयार की गई सूची को तहसीलदार द्वारा जिला कलक्टर को प्रेषित किया जायेगा।
4. ऐसी प्राप्त सूचनाओं को जिला कलक्टर संकलित करेंगे तथा उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग में ली गई चारागाह की क्षतिपूर्ति यथा संभव एक ही स्थान पर सिवायचक भूमि से की जायेगी।
5. इस कार्यवाही के लिये जिला कलक्टर सम्पूर्ण जिले में चारागाह भूमि को चिन्हित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि 100 वर्षों के लिये चारागाह भूमि उपलब्ध रहे।
6. जिला कलक्टर अतिक्रमित चारागाह भूमि जो आवासीय प्रयोजनार्थ कार्य में ली गई है, को सिवायचक में परिवर्तन राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 अनुसार केवल एक ही बार वर्गीकरण परिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।
7. यदि ग्राम पंचायत में सिवायचक भूमि उपलब्ध है तो चारागाह भूमि के समतुल्य सिवायचक भूमि चारागाह के रूप में आरक्षित करेंगे। जिला कलक्टर द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होगा कि किसी भी सूरत में जिले में कहीं भी चारागाह भूमि का क्षेत्रफल इस संबंध में निर्धारित मानको से कम नहीं हो पाये।
8. जिला कलक्टर चारागाह भूमि वर्गीकरण परिवर्तन कर सिवायचक भूमि को सेट अपार्ट कर पंचायत के आवंटन करते समय संबंधित ग्राम पंचायत को पाबंद करेंगे कि वह एक परिवार को अधिकतम 100 वर्गमीटर से अधिक भूमि का पट्टा नहीं दिया जाये।

9. केवल ऐसे व्यक्ति जो आयकर दाता नहीं है इस पालिसी के तहत पट्टा प्राप्त करने के पात्र होंगे।
10. जिला कलक्टर चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसे लोगों को नियमित इस शर्त के अध्यक्षीन करेंगे कि इस प्रकार नियमित किये गये आवास/भूमि को आगे स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा एवं यदि ऐसा स्थानान्तरण किया जाता है तो भूमि राज्य सरकार में स्वतः निहित हो जायेगी।
11. जिला कलक्टर संबंधित ग्राम पंचायत को यह भी निर्देश देंगे कि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे किसी परिवार के पक्ष में पट्टा नहीं दिया जाये यदि उस ग्राम पंचायत में उस परिवार के पास पूर्व में ही आवासीय मकान है।

रामचरन शर्मा,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।